आकाशवाणी शिमला

29.08.2024 / प्रादेशिक समाचार / 19:45 बजे

मुख्य समाचार

- **मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से प्रदेश में खुले स्कूलों को न तो बंद करेगी और न ही बेचेगी सरकार।**
- **राज्य सरकार राजधानी शिमला में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए कुछ विभागों को दूसरे जिलों में करेगी शिफ्ट।**
- **उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा–नदियों के चैनलाईजेशन के लिए 2 हजार 5 सौ 31 करोड़ रूपए के प्रौजेक्ट केन्द्र के पास लम्बित।**
- **विधानसभा में शराब के ठेकों की नीलामी पर हंगामा–न्यायिक जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन से किया वाकआउट।**

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से प्रदेश में जितने भी स्कूल खुले हैं, उन्हें सरकार न तो बंद करेगी, न ही उनके नाम बदले जाएंगे। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने आज सदन में विधायक विनोद कुमार और विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार किसी भी स्कूल को लीज पर नहीं देगी और न ही उन्हें बेचेगी। मुख्मयंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने जो अटल आदर्श विद्यालय बनाने शुरू किए थे उनका काम जारी है और बजट की उपलब्धता के अनुसार इनके कार्य को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि पूर्व की जयराम सरकार के 5 सालों के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार शिक्षा के साथ हिमाचल के हितों को बेचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं और स्कूल को लीज पर देने के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर फिर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया व नारेबाजी भी की।

इससे पहले, शिक्षा मंत्री की गैरमौजूदगी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक विपिन परमार व विनोद कुमार के मूल सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में कुल 3 अटल आदर्श विद्यालय निर्माणाधीन हैं। इनके निर्माण के लिए 70 करोड़ की राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि तीन वर्षों में किसी भी अटल आदर्श विद्यालय के लिए भूमि का चयन नहीं किया गया है। वर्तमान में केवल तीन जगह अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से एक भी विद्यालय अभी तक पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है। विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजधानी शिमला में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए यहां से कुछ कार्यालयों को दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जाएगा। इससे जहां शहर से दबाव कम होगा, वहीं कर्मचारियों की भी आवास की समस्या का समाधान भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे कई भवन खाली पडे हैं, जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कार्यालय शिफ्ट करने से वे इस्तेमाल में आएंगे। विधायक सुरेश कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नदियों के चैनलाइजेशन के लिए 2 हजार 5 सौ 31 करोड़ रुपए के 12 प्रोजेक्ट केंद्र के पास पिछले काफी समय से लंबित हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्टों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन पैसे नहीं मिले हैं। इससे प्रोजेक्टों का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीर खड्ड की चैनलाइजेशन का एक सौ 57 करोड़ 66 लाख रुपए का प्रोजेक्ट 2020 को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया

था। अग्निहोत्री ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने सारा पैसा जलजीवन मिशन में डाल दिया है और इस वजह से प्रदेश को न तो चैनेलाइजेशन और न ही सीवरेज व ड्रेनेज के लिए पैसा मिल रहा है। उप–मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल से प्रोजेक्ट केंद्र में लंबित हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर से कहा कि वह मुख्यमंत्री और उनके साथ दिल्ली चले और प्रोजेक्टों का पैसा दिलाने में सरकार की मदद करे।

संकल्प

प्रदेश में अवैध कटान को रोकने के लिए सरकार डीजल, पेट्रोल से चलने वाले कटरों के लाइसेंस बनाने पर नीति तैयार होगी। जंगलों के आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार महिला मंडलों को जंगलों को बढ़ाने की जिम्मेवारी देगी और इसके लिए उन्हें प्रोस्ताहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में विधायक डॉक्टर जनक राज और सुखराम चौधरी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नीति बनाने के संदर्भ में लाए गए संकल्प के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले साल होने वाले पौधारोपण पर नीति बनाई है कि जंगलों में 60 फीसदी फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस संकल्प में पक्ष व विपक्ष के कुल 12 सदस्यों ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट दोनों सदस्यों ने अपना संकल्प वापस ले लिया।

मुख्यमंत्री

प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों और बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन–भत्ते अगले दो महीने तक विलंबित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए विधानसभा में आज इस संबंध में एक विशेष वक्तव्य दिया। उन्होंने विधायकों से भी स्वेच्छा से इसे दो माह के लिए विलंबित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023–24 में 8 हजार 58 करोड़ रुपये थी वह इस वर्ष 18 सौ करोड़ रुपये कम हो कर 6 हजार 2 सौ 58 करोड़ रुपये हो गई है। अगले वर्ष में यह 3 हजार करोड़ रुपये और कम हो कर 3 हजार 2 सौ 57 करोड़ रुपये रह जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बन्द हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 3 हजार करोड़ की आय कम हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीएस बहाल करने के कारण राज्य की उधार लेने की सीमा भी लगभग 2 हजार करोड़ से कम कर दी गई है और इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने और गैर उत्पादक खर्चों को कम करने का प्रयास किया है।

वाकआउट

प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में शराब के ठेकों की नीलामी का मामला गूंजा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान नई शराब नीति में ठेकों के आवंटन का मामला उठाया और सरकार पर बड़े स्तर पर कथित भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में चार साल तक ठेकों को नीलामी नहीं की गई और सिर्फ लाइसेंस को रिन्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पांच साल के कार्यकाल में ठेकों से 6 सौ 65 करोड़ 42 लाख की आय हुई, जबकि कांग्रेस के एक साल के कार्यकाल में शराब के ठेकों की नीलामी से सरकार ने 4 सौ 85 करोड़ 18 लाख रुपए का राजस्व जुटाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के ठेकों की नीलामी पूरी पारदर्शी तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि ठेकों के आवंटन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया गया और कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है। इससे पहले, विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि पांच जिलों में शराब के ठेकों की नीलामी में मिलीभगत से घोटालों

का आरोप लगाया। रणधीर शर्मा ने सरकार के ध्यान में लाया कि प्रदेश में कई ठेकेदार शराब की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं।

इस पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की ज्यादा कीमत वसूलने पर सरकार ने 25 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। इस पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठ कर ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग करते हुए नारेबाजी कर सदन से बाहर चले गए।

निधन

वरिष्ठ पत्रकार व हिन्दुस्तान टाईम्स के प्रमुख सम्पादक गौरव बिष्ट का बीती रात हृदयघात के कारण शिमला में आकस्मिक निधन हो गया। वे 50 वर्ष के थे और पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वरिष्ठ पत्रकार गौरव बिष्ट के निधन पर शोकोदगार प्रस्तुत करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इससे पहले जुलाई माह में टाईम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सहायक सम्पादक आनंद बोध और जून माह में अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता विपिन काला के निधन पर भी शोक जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरव बिष्ट, आनंद बोध और विपिन काला ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च मापदण्डों को अपनाकर निर्भीक होकर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों के नैतिक दृष्टिकोण पत्रकारिता कौशल और सामाजिक सरोकार के प्रति किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने भी गौरव बिष्ट के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

सुखविंदर सिंह

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वे आज शिमला में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ सोलन जिला के नालागढ़ में निर्माणाधीन एक मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल को हरित उर्जा राज्य बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगा।